

## मोहन कैबिनेट- बड़े निर्णय

- मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर
- GIS-2025 के पहले सरकार के कई बड़े फैसले
- सरकार ने 07 नई नीतियों को दी मंजूरी
- प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए होगा अनुकूल माहौल
- मोहन सरकार ने जारी की नई नीतियां
- नई नीतियों से व्यापार और निवेश होगा आसान
- नई MSME और नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी
- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी नई नीति
- एकीकृत टाउनशिप के लिए बनाए नये नियम
- मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति को भी कैबिनेट की हरी झंडी

### नई MSME नीति को मंजूरी

- मप्र की नई MSME विकास नीति घोषित
- नई MSME नीति से प्रदेश में 86 लाख रोजगार का होगा सृजन
- ईज ऑफ डुइंग को प्रोत्साहित करेगी मोहन सरकार
- ईज ऑफ डुइंग को मिलेगा प्रोत्साहन
- 53 हजार करोड़ के निवेश का रखा लक्ष्य
- नवीन उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन
- मशीनरी-बिल्डिंग में निवेश पर 40 फीसदी सब्सिडी
- मशीनरी में 10 करोड़ तक निवेश पर महिलाओं को सब्सिडी
- अजा/अजजा/महिला उद्यमी को 48 और 52 फीसदी सब्सिडी
- 10 करोड़ से अधिक का उद्योग लगाने पर अनुदान
- निवेशकों को 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान मिलेगा
- टेक्सटाइल में निवेश करने वालों को मिलेगा विशेष पैकेज
- निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की पहल
- माल ढुलाई में 40 लाख तक की प्रतिवर्ष सहायता
- 5 वर्षों तक माल ढुलाई में मिलेगी आर्थिक सहायता

- निर्यात संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 50 लाख तक की मदद
- MSME नीति में रोजगार सृजन पर मिलेगा अनुदान
- 10 करोड़ से अधिक के उद्योगों पर मिलेगा अनुदान
- 100 से अधिक रोजगार देने पर 1.5 गुना अतिरिक्त अनुदान
- रिसाइक्लिंग इकाई के लिए 2 करोड़ तक की मदद
- ETP के लिए 2.5 करोड़ तक की मिलेगी मदद

#### **मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना**

- मोहन सरकार ने की स्टार्टअप नीति की घोषणा
- स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देगी मोहन सरकार
- स्टार्टअप से इकॉनोमी को लगेंगे पंख
- सर्टिफाइड स्टार्टअप्स की संख्या होगी 10 हजार
- स्टार्टअप के माध्यम से 1 लाख 10 हजार रोजगारों का लक्ष्य

#### **मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2025**

- इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग बढ़ाने पर जोर
- ई-वाहन की खरीदी पर मिलेगी कई तरह की छूट
- सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन खोलने पर भी मिलेगी सब्सिडी
- टेंडर के जरिए सरकारी भूमि पर खोल सकेंगे चार्जिंग स्टेशन
- पॉलिसी अवधि में 80 प्रतिशत सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक करना

#### **मप्र एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को मंजूरी**

- रियल एस्टेट विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहन
- किफायती आवासों की जरूरतें पूरी की जाएंगी
- भूमि पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा
- भूमि मालिक भूमि पुलिंग के जरिए बना सकेंगे टाउनशिप
- EWS और BPL वर्ग के लिए रखना होगा आरक्षण
- 15 फीसदी आवास दोनों वर्गों को देना अनिवार्य
- टाउनशिप में 10 फीसदी पार्क और खुले स्थान का प्रावधान
- राज्य की अधोसंरचना विकास में मिलेगी मदद

## विमानन नीति को मंजूरी

- विमानन में नये निवेश की संभावना बढ़ाएगी सरकार
- नई नीति में एयर कार्गो को मिलेगा बढ़ावा
- इंदौर-देवास-उज्जैन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की योजना
- शैक्षणिक संस्थानों में विमानन पाठ्यक्रम शुरू करने जोर
- हवाई अड्डा सह एरोट्रोपोलिस का होगा विकास
- एरोट्रोपोलिस से रोजगार के बढ़ेंगे अवसर
- युवाओं और महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
- कृषि उत्पादन क्षेत्रों में 'कृषि उड़ान क्लस्टर' बनेंगे
- एयर कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास
- मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा विकसित
- औद्योगिक विस्तार के लिए बनेंगे एयर कार्गो सेक्टर